जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 249 प्रभात बीकानेर, शनिवार 4 अप्रैल, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

'संसद का तीन दिन का विशेष सत्र, एक ''चुनावी सत्र'' है'

कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा इस तीन दिवसीय सत्र में महिला आरक्षण विधेयक व लोकसभा की सीटों के परिसीमन के आड़ में सीटों की संख्या बढ़ाने का विधेयक ''बुलडोज़'' करना चाहती है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। कांग्रेस ने आज कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को होने वाला संसद का विशेष सत्र आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। पार्टी ने कहा कि इसका उद्देश्य इस महीने के अंत में होने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित करना है।

कांग्रेस ने संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन में किसी भी जल्दबाजी के प्रति चेतावनी दी और कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और सरकार को इसे सावधानी से संभालना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया संशोधन तमिलनाडु और केरल जैसे कई राज्यों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है।

पार्टी महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि सरकार महिलाओं के आरक्षण विधेयक से संबंधित संशोधनों पर कांग्रेस के साथ चर्चा करना चाहती है।

- **कांग्रेस की पुरानी ''थ्योरी'' है कि परिसीमन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इससे दक्षिण भारत के राज्यों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का भारी राजनीतिक नुकसान होगा।**
- **कांग्रेस का यह भी आरोप है कि संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू, दो-तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर प्रस्तावित कर चुके हैं कि सरकार कांग्रेस से विशेष सत्र के बारे में विचार करना चाहती है, पर, हर बार खड़गे, एक ही जवाब दे रहे हैं कि अलग से कांग्रेस से बातचीत करने के बजाए एक सर्वदलीय बैठक आहूत करें, जिसमें पूरे विपक्ष को इन मुद्दों पर अपनी-अपनी सोच सामने रखने का मौका मिले।**

जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे ने रिजिजू को जवाब दिया और सुझाव दिया कि अलग-अलग पार्टियों से मिलने के बजाय सरकार 29 अप्रैल के बाद सभी पार्टियों की बैठक बुलाए, जब पांच राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को सभी विपक्षी दलों ने सरकार से इसी तरह की बैठक 29 अप्रैल के बाद बुलाने का अनुरोध किया था, क्योंकि तब तक अधिकांश पार्टियां विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगी।

रमेश ने बताया कि रिजिजू ने 26 मार्च को फिर से खड़गे को लिखा और कहा कि सरकार प्रस्तावित संविधान संशोधन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ चर्चा करना चाहती है। खड़गे ने पुनः जवाब दिया और कहा कि सरकार को अलग बैठक करने के बजाय सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने मनमाने तरीके से 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया, जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर होगा।

उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को 2023 में पास किया गया था और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की मांग की थी। रमेश ने कहा, ''जैसे डबल इंजन सरकार के दावे हैं, भाजपा अब महिलाओं के आरक्षण से दोगुना लाभ लेना चाहती है।''

जयराम रमेश ने कहा कि सरकार लगभग 30 महीने बाद जागी है और 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सरकार 15 दिन और इंतजार कर विपक्षी दलों से परामर्श कर सकती थी और उसके बाद सत्र बुला सकती थी। उन्होंने सरकार की समयसीमा पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के आदेश में संशोधन किया

जयपुर, 3 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की 5 और 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों को शामिल करने के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों के दायरे को सीमित करते हुए, सिर्फ याचिकाकर्ता

- **अब वर्ष 2024 के केवल उन अभ्यर्थियों को 2025 की परीक्षा में शामिल किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हैं।**

को ही परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज मल मीणा की ओर से दायर याचिका में आरपीएससी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत नहीं आने वाले अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि भर्ती परीक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ईरान वॉर से हट गए तो क्या होगा, चिंतित हैं अमेरिका के मित्र राष्ट्र

ये देश चाहते हैं, पहले होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित और मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। अमेरिका के सहयोगी इस संभावना को लेकर चिंतित हैं कि यदि अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट से मुक्त व्यापारिक आवाजाही सुनिश्चित किए बिना ईरान युद्ध से बाहर निकल गया तो क्या होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बार-बार नाटो देशों की इस बात के लिए आलोचना की है कि वे ईरान के नियंत्रण से जलमार्गों को मुक्त कराने के लिए अपनी सेनाएं तैनात करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ईरान संघर्ष में अमेरिका के लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं।

गुरुवार को 40 यूरोपीय, एशियाई और मध्य-पूर्वी देशों के अधिकारियों के साथ-साथ कैनडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधियों ने एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दो उद्देश्य थे: पहला, अमेरिका पर दबाव बनाना कि वह ईरान के साथ युद्धविराम वार्ता में होर्मुज़ का समाधान शामिल करे। दूसरा, उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करना, क्योंकि ट्रंप के सहयोग की संभावना कम मानी जा रही थी। इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं था, क्योंकि ट्रंप पहले ही यह कह चुके थे कि ''जलमार्गों की सुरक्षा करना अमेरिका का काम नहीं है।'' उन्होंने हाल ही में सहयोगियों से कहा था, ''जाकर अपना खुद का तेल लाओ।''

- **अमेरिका के मित्र राष्ट्रों व एशिया के कुछ देशों ने इस बारे में एक मीटिंग कर दो मुद्दे तय किए।**
- **पहला मुद्दा है कि अमेरिका पर दबाव डाला जाए कि वह ईरान के साथ सीज़फायर वार्ता में होर्मुज़ से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बात करे। दूसरा मुद्दा है कि सुरक्षित आवाजाही के लिए सभी उपलब्ध कूटनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए।**
- **पर, ट्रंप नाटो के अपने सहयोगी देशों से काफी नाराज़ हैं, खासकर, इसलिए क्योंकि ईरान वॉर के दौरान इन देशों ने अमेरिका का सहयोग करने से साफ इन्कार कर दिया है।**

इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन की विदेश सचिव इवेट कूपर ने की। इसका उद्देश्य था, ''सभी संभावित कूटनीतिक और राजनीतिक उपायों का आकलन करना, ताकि नौवहन की स्वतंत्रता बहाल की जा सके, फंसे हुए जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही फिर से शुरू हो सके।''

गठबंधन देशों के सैन्य योजनाकारों ने यह भी तय किया है कि वे अगले सप्ताह बैठक करेंगे, जिसमें यह चर्चा होगी कि लड़ाई समाप्त होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नेशनल और स्टेट हाईवे सहित जयपुर को जोड़ने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाएं'

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि ''जहां जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए गए हैं, उन मामलों में कोई भी सिविल न्यायालय या जेडीए ट्रिब्यूनल हस्तक्षेप नहीं करेगा''

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 3 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर डवलपमैंट अथॉरिटी (जेडीए) की अतिक्रमण विंग को आदेश दिए हैं कि वह नेशनल और स्टेट हाईवे पर हुए अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए कदम उठाए, साथ ही जयपुर शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों व आसपास की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। कार्यवाहक न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे को लेकर विजय कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाईकोर्ट ने यह आदेश सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने के मुद्दे पर विजय कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिए।**
- **उधर जेडीए प्रशासन ने सिरसी रोड पर खातीपुरा तिराहे से झाड़खंड मोड़ तक अतिक्रमण हटाने को लेकर 6 सप्ताह का समय हाईकोर्ट से मांगा है।**

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया है। ऐसे में जिन मामलों में जेडीए ने मास्टर प्लान में आने वाली भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए अधिनियम की धारा 72 के नोटिस जारी किए हैं, उन मामलों में कोई भी सिविल न्यायालय या जेडीए ट्रिब्यूनल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके साथ ही, अदालत ने जेडीए को कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश था। अफगान-ताजिकिस्तान बॉर्डर पर भी 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केन्द्र जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था। भूकंप के झटके

- **भूकंप का केन्द्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 नापी गई।**

चार देशों- भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में महसूस किए गए।

किसी तरह के जान-माल के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में रात 9: 46 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग घरों से बाहर आ गए।

अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान एफ-15 मार गिराया ईरान ने

इस विमान में दो पायलट होते हैं, पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका ने भारी ''सर्च और रेस्क्यु'' ऑपरेशन शुरु किया

-अंजन रॉय--
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। अमेरिका को एक नया झटका देते हुए ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में एक-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। विमान के पायलट की तलाश के लिए खोज अभियान शुरू किया गया है।

अमेरिका और इज़रायल के अधिकारियों ने हाल ही में विमान के नुकसान की पुष्टि की है। अमेरिकी एजेंसियां कथित तौर पर पायलट और चालक दल की तलाश के लिए व्यापक खोज अभियान चला रही हैं।

यह अमेरिका के लिए एक और झटका है, क्योंकि वह ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करता रहा है, जिसमें ईरान की एंटी-एयरक्राफ्ट क्षमताओं की निगरानी भी शामिल है। अमेरिकी विमानों को आमतौर पर अपने मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम से अत्यंत सटीक जानकारी और रक्षात्मक खुफिया सहायता मिलती है, जिससे वे दुश्मन के हमलों से बच सकें।

- **इस विमान को मार गिराने से अमेरिका व इज़रायल के लिए भारी अटपटी स्थिति पैदा की है, क्योंकि जिस स्थान पर ईरान ने इस विमान को मार गिराया है, उस स्थान को अमेरिका व इज़रायल दोनों पूर्णतया अपना आधिपत्य में होने का दावा करते रहे हैं।**
- **दूसरी ओर ईरान ने घोषणा की है कि वह अमेरिका के ''मित्र देश'' कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन आदि के इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंक्स जैसे महत्वपूर्ण सड़क व पुल को अपना टारगैट बनायेगा, बमबारी के लिए।**
- **इससे काफी दहशत फैली है, खाड़ी देशों में और लड़ाई सिमटने के बजाय और व्यापक होती जा रही है।**

एफ-15 विमान में दो पायलट होते हैं, इसलिए गिराए गए विमान में भी दो पायलट सवार थे। अमेरिका ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है और कई विमान पहले से ही उड़ान भर रहे हैं। बचाव दल में आमतौर पर फिक्स्ड-विंग विमान और हेलीकॉप्टर, दोनों शामिल होते हैं।

कुछ ईरानी समाचार एजेंसियों ने दावा किया है कि उन्होंने बचाव अभियान के हिस्से के रूप में अमेरिका के बड़े हेलीकॉप्टरों को देखा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ईरानी हमले के बाद इन टीमों को पीछे हटना पड़ा।

अमेरिकी पायलटों को ऐसी परिस्थितियों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बच निकलना और गिरफ्तारी से बचाव शामिल है। इसके अलावा, उनके पास ऐसे सिग्नलिंग उपकरण होते हैं, जो उनकी लोकेशन अमेरिकी बलों को बता सकते हैं। हालांकि ये बचाव अभियान स्वयं बचाव दल और उनके विमानों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं।

ईरान ने अब तक पायलट और चालक दल के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, सिवाय इसके कि उनके बारे में जानकारी देने पर भारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

माल्दा में जजों के घेराव की जाँच एनआईए करेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जाँच एनआईए (राष्ट्रीय जाँच एजेंसी) को सौंप दी।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को ''सबसे अधिक ध्रुवीकृत राज्य'' बताते

- **चुनाव आयोग ने 2 अप्रेल को इस संबंध में एनआईए को चिट्ठी लिखी है।**

हुए राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की, जब मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों, जो एसआईआर कार्य में लगे थे, प्रदर्शनकारियों द्वारा बंधक बनाए गए। कोर्ट ने सीबीआई या एनआईए द्वारा इस घटना की जाँच कराये जाने के निर्देश दिये। 2 अप्रैल को लिखे एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने एनआईए को सुप्रीम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल में भाजपा को यह साबित करना भारी पड़ रहा है कि वह मछली विरोधी नहीं है

तृणमूल ने चुनाव प्रचार को भ्रष्टाचार, रोजगार व सत्ता विरोध से हटाकर ''मछली खाने'' के मुद्दे पर केन्द्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के चुनावी जल में मछली अब सिर्फ थाली तक सीमित नहीं रही; यह राजनीति का केन्द्र बन गई है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) बंगाली गौरव को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा इस बात से बचने के लिए संघर्ष कर रही है कि वह 'माछे भाते बंगाली' कहावत के गलत साइड पर न आ जाए।

विशालकाय मछली 'कतला' से लेकर 'इलीश', पाबदा और चिंगरी को राजनीतिक भाषणों में प्रमुख स्थान मिल रहा है, और मछली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एक अप्रत्याशित, लेकिन प्रभावशाली प्रतीक बन गई है। भोजन की आदतें अब पहचान, संस्कृति और ''असली'' बंगाली का प्रतिनिधित्व करने वाले मुद्दों पर तीव्र संघर्ष में बदल गई हैं।

पुरानी बंगाली कहावत 'माछे भाते बंगाली', जिसका अर्थ है कि एक बंगाली की पहचान मछली और चावल के सेवन से होती है, इस चुनाव में विभिन्न दलों के लिए असली (डि फ़ैक्टो) नारा बन गई है।

टीएमसी ने इस भावना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है, यह तर्क देते हुए कि भाजपा, जिसे टीएमसी हिंदी भाषियों और उत्तर भारत की शाकाहार को प्रोत्साहित करने वाली राजनीति से जोड़ती है, पश्चिम बंगाल के लिए सांस्कृतिक रूप से परायी तथा

- **ममता बनर्जी अपनी रैलियों में जोर शोर से दावे कर रही हैं कि भाजपा बाहरी पार्टी है, यह बंगाल में मछली, मीट व अंडे पर रोक लगा देगी, उन्होंने नारा दिया है ''माछे भाते बंगाली'' अर्थात बंगाली की पहचान मछली, चावल खाने से होती है।**
- **तृणमूल के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर भी मछली के व्यंजनों की तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। यही नहीं शाह ने जब बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन रूकने की बात कही तो उनसे मछली के व्यंजनों का तुल्फ उठाने का आग्रह भी किया गया।**
- **भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तृणमूल को मात देने के लिए। पार्टी ने सफाई दी है कि वह मछली आदि के सेवन पर रोक नहीं लगाएगी। उन्होंने तृणमूल पर चुनाव प्रचार को भटकाने और खाने के मैनु कार्ड तक लाने का आरोप लगाया।**

विदेशी है और यदि वह सत्ता में आती है, तो मछली, मांस और अंडे पर प्रतिबंध लगा सकती है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में इस हमले को तेज करते हुए कहा, ''वे आपको मछली नहीं खाने देंगे। आप मीट नहीं खा सकते, अंडे नहीं खा सकते, बंगाली में बात नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, तो वे आपको बांग्लादेशी कहेंगे।'' इस तरह से बनर्जी ने भोजन, भाषा और बंगाली पहचान को एक राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा।

इस आरोप से टीएमसी अपने अभियान को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता विरोध से हटाकर, उस क्षेत्र में ले गई है, जहाँ वह अधिक सहज महसूस करती है, यानी ''बंगाली उपराष्ट्रीयता।'' मछली अब केवल भोजन नहीं, बल्कि बंगाली गौरव का प्रतीक बन गई है।

पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स ने उस समय इलीश भापा, पाबदा झाल, चिंगरी मलाई करी और कोषा मंगशो जैसे व्यंजनों की तस्वीरें पोस्ट कीं, जब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 15 दिन बिताएंगे।

टीएमसी के एक पोस्ट में शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''पश्चिम बंगाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मालदा कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

कोलकाता, 03 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मालदा हिंसा में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान और पूरा मामला एनआईए को रेफर होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मालदा घटना पर

- **पुलिस ने बताया कि आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को एनआईए को सौंप दिया गया है।**

उत्तरी बंगाल के एडीजी के. जयरामन के अनुसार अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा में 19 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि हिंसा भड़काने वाले मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को अरेस्ट किया गया है। वह अभी बागडोगरा में हिरासत रखा गया है। एडीजी के. जयरामन ने बताया कि उसे यहां लाया जा रहा है। आगे एनआईए इस मामले की जांच अपने हाथ में लेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)